दैनिक
लोक टुडे
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 341 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | शुक्रवार 26 जून 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

वेनेजुएला में भूकंप के 2 बड़े झटके, 164 की मौत

तीव्रता 7.5 और 7.2 रही; मृतकों की संख्या 10,000 होने की आशंका

करकस, वेनेजुएला

वेनेजुएला में 39 सेकेंड में दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.04 बजे 7.2 और 6.05 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे। लोगों ने बताया कि भूकंप के बाद 60 सेकेंड तक शहर हिलता रहा। 20 ऑफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 164 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 घायल हैं। ये भूकंप ऐसे दिन आए, जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, 30% आशंका एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। दोनों भूकंप राजधानी करकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गईं या खतरनाक तरीके से झुक गईं। करकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का गुबार उठता दिखाई दिया।

126 साल में सबसे बड़ा भूकंप, देश में इमरजेंसी

वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है, इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया।

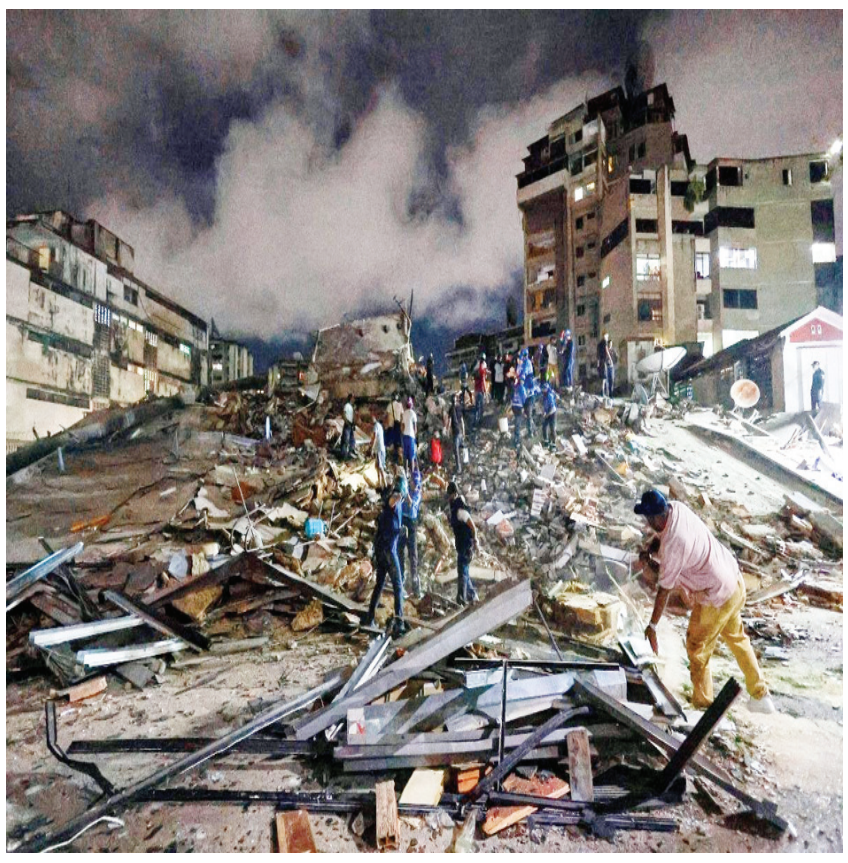

वेनेजुएला के ला ग्वेइरा शहर में 100 से ज्यादा इमारतें ढहीं

वेनेजुएला में आए दो बड़े भूकंप और उसके बाद आए कई आफ्टर शॉक से सबसे अधिक तबाही ला ग्वेइरा राज्य में हुई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, यहां 100 से ज्यादा इमारतें ढह गई हैं। इससे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने इस इलाके को सबसे ज्यादा प्रभावित बताते हुए आपदा क्षेत्र घोषित किया था। रॉड्रिगेज ने संयुक्त राष्ट्र की सभी बचाव टीमों को राहत और बचाव अभियान में शामिल होने की अनुमति भी दे दी है। ये टीमें दूसरे देशों से आई राहत टीमों को जरूरी सामान, संसाधन और दूसरी मदद उपलब्ध कराएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बचाव दल ला ग्वेइरा और राजधानी काराकास में तैनात किए जाएंगे। वहीं, बाकी इलाकों में राहत और बचाव का काम स्थानीय टीमों और सिविल प्रोटेक्शन के जिम्मे रहेगा।

वेनेजुएला में 1900 के बाद सबसे बड़ा भूकंप

वेनेजुएला या उसके आसपास के तटीय क्षेत्र में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप पिछले 100 से अधिक साल में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इससे पहले वर्ष 1900 में 7.7 तीव्रता का सैन नार्सिसो भूकंप आया था। उसका केंद्र भी कैरेबियाई तट के पास था। उस भूकंप में करकस की कई चर्च, सरकारी इमारतें और घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। USGS के अनुसार उसमें 21 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस समय द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 300 इमारतें ढह गई थीं और बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक तंबुओं में रहना पड़ा था।

'अर्थक्वेक डबलट' क्या है

दोनों भूकंप बहुत कम समय और बहुत कम दूरी के भीतर आए। वैज्ञानिक ऐसी घटना को अर्थक्वेक डबलट कहते हैं। इसमें दो बड़े भूकंप लगभग एक ही इलाके में और कुछ सेकंड या मिनट के अंतराल पर आते हैं। ऐसे मामलों में दूसरा भूकंप अक्सर पहले से अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पहली घटना से कमजोर हो चुकी इमारतें दूसरे झटके में ढह जाती हैं।

27 साल पहले हुए भूस्खलन में ला ग्वाइरा शहर में 15 हजार लोग मारे गए थे

बुधवार को आए दोनों शक्तिशाली भूकंपों का सबसे ज्यादा असर ला ग्वाइरा शहर में दिखाई दिया। यह वेनेजुएला की राजधानी करकस के पास स्थित एक पोर्ट सिटी है। साल 1999 में यहां मूसलाधार बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ था। पहाड़ियों पर बनी बस्तियां मलबे में दब गई थीं और कम से कम 15 हजार लोगों की मौत हुई थी। उस समय यह हादसा तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज के सत्ता संभालने के कुछ ही महीनों बाद हुआ था। अभी यह जो हादसा हुआ है वह डेल्सी रोड्रिगेज के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद हुआ है।

वेनेजुएला में इतना भीषण भूकंप कैसे आया

वेनेजुएला ऐसे इलाके में है, जहां भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसकी वजह यह है कि यहां कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलती हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (स्तर) के मुताबिक, बुधवार को आए दोनों भूकंप इन्हीं प्लेटों के टकराने और खिसकने से आए। आसान भाषा में समझें तो जमीन के नीचे बड़ी-बड़ी चट्टानों की परतें (टेक्टोनिक प्लेटें) लगातार धीरे-धीरे खिसकती रहती हैं। लेकिन जब ये अचानक झटके से खिसकती हैं, तो जमीन हिलने लगती है और भूकंप आ जाता है। स्तर का कहना है कि भूकंप सिर्फ एक जगह नहीं आता। जमीन के नीचे कई किलोमीटर लंबे हिस्से में प्लेटें खिसकती हैं, जिससे तेज झटके महसूस होते हैं। एजेंसी के मुताबिक, इन दोनों भूकंपों के बाद भी जमीन के नीचे हलचल जारी है। इसलिए अगले कुछ दिनों में और झटके आ सकते हैं। इनमें से कुछ झटके काफी तेज भी हो सकते हैं।

लोकतंत्र सेनानियों को तोहफा ; मासिक पेंशन और चिकित्सा सहायता में बढ़ोतरी, 1140 को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने 'संविधान हत्या दिवस' पर की घोषणा, रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा भी मिलेगी

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपातकाल के दौरान देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दी जाने वाली मासिक चिकित्सा सहायता को भी 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। इस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवाड़ी, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा और बाबा बालमुकुंद आचार्य सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के योगदान की सराहना की।

'संविधान हत्या दिवस' समारोह में हुई घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह बड़ी घोषणा गुरुवार को जयपुर के दुर्गापुरा में 'संविधान हत्या दिवस' के अवसर पर आयोजित एक विशेष 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' के दौरान की। इस कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले कई वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया गया।

रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात

पेंशन और चिकित्सा भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक और बड़ी सुविधा का ऐलान किया। अब इन सेनानियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

एक नजर में बदलाव

मासिक पेंशनः 20,000 से बढ़कर अब 25,000 हुई (5,000 की वृद्धि)।
चिकित्सा सहायताः 4,000 से बढ़कर अब 5,000 हुई (1,000 की वृद्धि)।
अतिरिक्त लाभः राजस्थान रोडवेज की बसों में जीवनभर मुफ्त सफर की सुविधा।

'आपातकाल ने कुचली थी लोकतंत्र की आत्मा'

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, '25 जून 1975 को देश में लगाया गया आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक काला धब्बा है, जिसने संविधान और लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का काम किया था।' उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार लोकतंत्र सेनानियों के बलिदान और कड़े संघर्ष को हमेशा नमन करती है और यह कदम उनके प्रति राज्य सरकार के इसी सम्मान को प्रदर्शित करता है।

योजना में राज्य में कुल 1140 लाभार्थी

राजस्थान में वर्तमान में कुल 921 लोकतंत्र सेनानी हैं। इसके अलावा, दिवंगत सेनानियों के 219 आश्रित (पति/पत्नी) भी हैं। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य विभाग द्वारा विधानसभा में दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत राज्य में कुल 1140 लाभार्थी हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मासिक सम्मान पेंशन और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

काम न काज, फिर भी पूरा वेतन : राजस्थान में एपीओ के 'आराम' पर रोक, अब 30 दिन में मिलेगी पोस्टिंग

वित्त विभाग का बड़ा फैसला: नियम 25-A में बदलाव, जवाबदेही बढ़ने के साथ रुकेगी राजकोष की बर्बादी, मनमर्जी से किसी को APO करने का खेल अब बंद

लोक टुडे। जयपुर

क्या आपने कभी ऐसी नौकरी की कल्पना की है, जहां आपको कोई काम न करना पड़े, लेकिन हर महीने की एक तारीख को पूरा वेतन और भत्ता आपके खाते में आ जाए? सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन राजस्थान के सरकारी तंत्र में इसे 'एपीओ' या पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा कहते हैं। हाल ही में राज्य के वित्त विभाग ने इस प्रथा पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सेवा नियम (RSR), 1951 के नियम 25-A के तहत नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत एपीओ की डेडलाइन तय करने के साथ लापरवाह अधिकारी की जवाबदेही भी तय की है।

आखिर क्या होता है यह APO?

जब किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला होता है और सरकार उसे तुरंत कोई नया पद या विभाग नहीं सौंपती, तो उसे 'एपीओ' घोषित कर दिया जाता है। तकनीकी रूप से इसका मतलब है कि कर्मचारी सरकार की 'प्रतीक्षा सूची' में है। नियमों के मुताबिक, एपीओ की इस अवधि को भी 'ऑन ड्यूटी' माना जाता है। यानी कर्मचारी को बिना कोई काम किए भी पूरा वेतन, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं।

राजस्थान में इस समय यह हैं हालात : 35 सीनियर अधिकारी और 12000 कर्मचारी एपीओ-

आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान में इस वक्त बिना कुर्सी-टेबल के वेतन उठाने वालों की एक पूरी फौज खड़ी है। राज्य के लगभग 35 सीनियर अधिकारी इस समय पोस्टिंग के इंतजार में हैं। इनमें केंद्र से लौटकर आए 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस रोहित कुमार समेत 8 आईएएस, 2 आईपीएस और भारतीय वन सेवा के 22 अफसर शामिल हैं।वहीं अगर छोटे-बड़े सभी विभागों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व) को मिला लिया जाए, तो राज्य में लगभग 12,000 कर्मचारी बिना किसी काम के सिर्फ एपीओ होने के कारण वेतन ले रहे हैं।

जनता की जेब पर भारी 'मुफ्त की सैलरी'

सोचिए, एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी का मासिक वेतन लाखों में होता है। जब दर्जनों आला अफसर और हजारों कर्मचारी महीनों तक बिना काम किए वेतन लेते हैं, तो राज्य के खजाने (यानी जनता के टैक्स के पैसे) पर हर महीने करोड़ों रुपए का अकारण बोझ पड़ता है। कई बार अधिकारी राजनीतिक खींचतान या प्रशासनिक लापरवाही के कारण भी महीनों तक एपीओ पड़े रहते हैं।

नई गाइडलाइन से यह बदलेगा

वित्त विभाग के नए नियमों ने इस 'आराम' पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। अब किसी भी कर्मचारी या अफसर को अधिकतम 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं रखा जा सकेगा। इस अवधि के भीतर उन्हें नई पोस्टिंग देना अनिवार्य होगा। अगर किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा एपीओ रहता है, तो उस अतिरिक्त अवधि का वेतन लापरवाही बरतने वाले अधिकारी की जेब से भी वसूला जा सकता है। साथ ही अब किसी को भी सिर्फ निजी नाराजगी या राजनीतिक द्वेष के चलते एपीओ नहीं किया जा सकेगा। आदेश जारी करने से पहले फाइल पर ठोस प्रशासनिक कारण लिखना होगा।

राजस्थान पुलिस में तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन; 403 उच्च पदों को मंजूरी

बजट घोषणा 2026-27 की समयबद्ध क्रियान्विति, चालक, बैंड और घुड़सवार विंग में अब तेजी से होंगे प्रमोशन

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस बेड़े के हित में एक बड़ा और संवेदनशील निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस की तकनीकी शाखाओं में लंबे समय से पदोन्नति के सीमित अवसरों से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत दी है। गृह विभाग, राजस्थान द्वारा जारी आधिकारिक स्वीकृति के तहत पुलिस के चालक (ड्राइवर), घुड़सवार और बैंड शाखाओं का कैडर पुनर्गठन कर 403 पदों को उच्च पदों में अपग्रेड कर दिया गया है। यह कदम मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2026-27 की समयबद्ध अनुपालना में उठाया गया है।

डीजीपी के प्रयासों से दूर हुआ बरसों का गतिरोध

पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार, तकनीकी संवर्ग के जवानों में सिविल पुलिस की तुलना में समयानुसार पदोन्नति न मिलने से लंबे समय से निराशा का माहौल था। इस शाखा के कई कॉन्स्टेबल सालों-साल एक ही पद पर काम करते रह जाते थे। पुलिस महानिदेशक (DGP) के विशेष और निरंतर प्रयासों के बाद इस विंग के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसे मुख्यमंत्री ने तत्काल मंजूरी देकर पुलिसकर्मियों की तरक्की का रास्ता खोल दिया।

जानिए किस विंग में बढ़े कितने उच्च पद

1. चालक (ड्राइवर) वर्ग (कुल 331 पद): सबसे बड़ी राहत इसी वर्ग को मिली है। इसमें पुलिस निरीक्षक (CI/CC) के 16 पद, उप निरीक्षक (SI/PC) के 62 पद और हेड कॉन्स्टेबल के 253 पद बढ़ाए गए हैं।
2. बैंड वर्ग (कुल 69 पद): इस विंग में उप निरीक्षक (SI/PC) के 17 पद तथा हेड कॉन्स्टेबल के 52 पदों की वृद्धि की गई है।
3. घुड़सवार वर्ग (कुल 03 पद): इस शाखा में उप निरीक्षक (SI/PC) स्तर के 3 नए उच्च पद बढ़ाए गए हैं।

पुलिसकर्मियों का बढ़ेगा मनोबल

इस फैसले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी संवर्ग के पुनर्गठन से अब इन विंग के जवानों को भी सिविल पुलिस की तरह समय पर प्रमोशन मिल सकेगा। इससे न केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों का मनोबल मजबूत होगा बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली में भी और अधिक दक्षता आएगी।

अभी तक सीमित रहे अवसर

तकनीकी संवर्ग में अभी तक सिविल, आईबी, दूरसंचार आरएसी/एमबीसी चालक, सिविल घुड़सवार और सिविल व आरएसी/एमबीसी बैंड में पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित होने से कार्मिकों में निराशा थी। इस संवर्ग में नियुक्त कॉन्स्टेबल लंबे समय से इसी पद पर कार्यरत हैं जबकि समान वर्ष में सिविल पुलिस में नियुक्त कॉन्स्टेबल पदोन्नति प्राप्त कर सहायक उपनिरीक्षक बन गए हैं।

सम्पादकीय

सूखे की आशंका

यह अच्छा हुआ कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो प्रभाव के चलते मानसून में कमी को देखते हुए सूखे की आशंका से निपटने के लिए फिर से बैठक की। इसके पहले उन्होंने एक बैठक इस माह के प्रारंभ में भी की थी। गत दिवस की बैठक में उन 315 जिलों की पहचान की गई, जो सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। इन जिलों में भी 111 ऐसे हैं, जहां सूखे का असर कहीं अधिक हो सकता है। नि:संदेह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए बारिश में कमी एक गंभीर चुनौती है। सूखे की आशंका केवल किसानों की ही समस्या नहीं बढ़ाएगी, बल्कि कमजोर फसल के नतीजे में अनाज के महंगे होने से आम आदमी भी प्रभावित हो सकता है। फसल उत्पादन में कमी को देखते हुए सरकार को खाद्य सुरक्षा के प्रति सचेत होना होगा। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि कमजोर मानसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। नि:संदेह बारिश में कमी के चलते चुनौती केवल सिंचाई के जल के अभाव के रूप में ही पैदा नहीं होगी, बल्कि देश के कुछ इलाकों में पेयजल संकट भी बढ़ सकता है। वैसे भी गर्मियों में देश के कई हिस्से इस संकट से दो-चार होते ही हैं। स्पष्ट है कि कृषि मंत्रालय के साथ जलशक्ति मंत्रालय को भी सक्रिय होना होगा।

अब जब सूखे की आशंका गहराती जा रही है, तब फिर उसके असर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। इस तैयारी के अनुकूल परिणाम तभी मिलेंगे, जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी। इसमें देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि इस बार बारिश कम होने जा रही है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो गया है कि किसानों को कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए आवश्यक सलाह और सहायता देने में देर न की जाए। इसी तरह यह भी देखा जाए कि जलाशयों के जल का समुचित उपयोग हो। यह सही समय है कि जल संरक्षण के साथ वर्षा का पानी बचाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। पानी की बर्बादी को रोकने के भी यथासंभव उपाय करने होंगे और इसमें हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। चूंकि अपने देश की समस्या यह है कि कृषि का एक बड़ा हिस्सा बारिश के जल पर निर्भर है, इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वर्षा जल संचयन संबंधी योजनाओं की समीक्षा हो।

इसकी कोशिश हर स्तर पर होनी चाहिए कि बारिश के जल का अधिकाधिक संचयन हो सके। चूंकि अल नीनो प्रभाव के अतिरिक्त जलवायु में लगातार परिवर्तन एक हकीकत है, इसलिए उससे उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के उपायों पर सतत ध्यान देने की रणनीति समय की मांग है। बारिश होते ही सूखे से निपटने के दीर्घकालिक उपायों की अनदेखी ठीक नहीं।

संपूर्ण दवा सुरक्षा शृंखला को कीजिए मजबूत

अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ़ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण शृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसी दवा प्रणाली बनाना है, जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की ज़िम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें।

अक्तूबर, 2025 में, मध्य प्रदेश के एक ज़िले में संदूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की ख़बरों ने देश को झकझोर दिया था। अब, जून, 2026 में, भारत सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और 'शेड्यूल के' से सभी सिरप को अनुमति सूची से हटा दिया है। 'शेड्यूल के' में गांवों या ऐसी जगहों पर, जहां पर आबादी एक हज़ार से कम है, गैर-फ़ार्मेसी दुकानों पर भी सिरप बिक्री को मंज़ूरी थी। अब पूरे देश में, दवा युक्त सिरप आम दुकानों पर नहीं रखी जा सकती और उनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची पर होना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी के बाद जांच हुई और कुछ नियामक पहल हुई। इस घटना की याद ने नीतिगत फ़ैसले को आकार दिया है। हालांकि, इसे मोटे तौर पर कफ सिरप की बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य किए जाने के फ़ैसले के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर दवा युक्त कफ सिरपों में (हर्बल सिरप को छोड़कर) ऐसे तत्व होते हैं, जिनकी खरीद या बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता हमेशा से थी। मगर, पालन नहीं किया जाता था। यह नीतिगत फ़ैसला स्पष्ट रूप से पर्ची की अनिवार्यता को सुदृढ़ करता है। सभी सिरपों में, भारत में सबसे अधिक गलत इस्तेमाल कफ़ सिरप का होता है। कई लोग बीमारी की सही शिनाख़्त करवाए बिना खुद से इन्हें खरीद लेते हैं, छूत से लगी सर्दी-खांसी में इनका इस्तेमाल करते हैं जबकि इनसे फायदा बहुत कम होता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद यह छोटे बच्चों को बार-बार खुराक दी जाती है। धारणा बना ली कि मीठा तरल नुकसानदायक प्रतीत नहीं होता। कुछ सिरप फार्मूलों में एंटीहिस्टामाइन, डिकंजेस्टेंट, सिडेटिव, ओपिओइड या अल्कोहल जैसे तत्व होते हैं, जो फ़ायदे के बजाय नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं। किशोरों और वयस्कों में भी कुछ किस्म के सिरप का गलत इस्तेमाल होता है। पर्ची की अनिवार्यता बनने से लोग आसानी से इन्हें नहीं खरीद पाएंगे, पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाएगा। फिर भी, यह कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा है। कई परेशान माता-पिता के लिए बच्चे की खांसी चिंताजनक हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाने पर अगर सिरप न लिखा जाए तो उन्हें अक्सर लगता है कि इलाज अधूरा रह गया। मरीज़ अक्सर कफ सिरप लिखने की मांग करते हैं और अगर डॉक्टर मना कर दे, तो कुछ परिवार किसी दूसरे डॉक्टर का रुख करते हैं, जो इसे लिख दे। पुरानी पर्चियों को भी संभालकर रखा जाता है और मिलते-जुलते लक्षणों के लिए वही दवा दोबारा खरीदने में इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसे हालात में, नियमों में यह बदलाव गलत इस्तेमाल को कम कर सकता है, पर्ची की अनिवार्यता होने को मजबूत करता है और गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को बदल सकता है।

बेशक, यह बदलाव स्वागतयोग्य है, लेकिन काफ़ी नहीं है। मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी मुख्य रूप से डॉक्टर की पर्ची न होने के कारण नहीं हुई थी। यह बच्चों तक संदूषित उत्पाद पहुंचने के कारण हुई। जब डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल—वे औद्योगिक रसायन, जो दवाओं में कदापि नहीं होने चाहिए—किसी सिरप में मिला दिए जाएँ, तो यह व्यवस्था-तंत्र की विफलता है, जिसकी ज़िम्मेदारी ऊपर स्तर पर बैठे नियामकों की है। इसमें कच्चे माल की खरीद, परीक्षण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और बाज़ार से उत्पाद हटाने जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक होती है। डॉक्टर की परामर्श पर्ची उपयोग को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन संदूषित खेप को सुरक्षित नहीं बना सकती।

अन्य देश इस बाबत उपयोगी सबक हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, खांसी और जुकाम की कुछ दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के उपलब्ध हैं, लेकिन नियामक दो साल से कम उम्र के बच्चों में इनके उपयोग पर चेतावनी देते हैं, और निर्माता आमतौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग के खिलाफ लेबल पर लिखा होता है। यूनाइटेड किंगडम में, कई खांसी और जुकाम की दवाएं छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं, जबकि छह से बारह वर्ष की आयु के बच्चों में उनका उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की देख-रेख में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी छोटे बच्चों में इसके उपयोग को हतोत्साहित किया है और लेबल पर बाकायदा चेतावनी छापने को कड़ा कर रखा है। ये देश दुर्घटना अवसर घटाने के लिए केवल डॉक्टर की पर्ची पर निर्भर नहीं हैं। वे आयु प्रतिबंध, चेतावनी लेबल, डाक्टरी परामर्श, विष नियंत्रण प्रणाली, प्रतिकूल घटना पर त्वरित सूचना और निगरानी उपायों का उपयोग करते हैं। भारत को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाइयां न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए, सिवाय कुछ दुर्लभ मामलों में विशेषज्ञ की सलाह पर। इनसे बड़े बच्चों के लिए, मानकीकृत देखभाल की शुरुआत, दिलासा देने, तरल पदार्थ देकर, जरूरत पड़ने पर बुखार नियंत्रण, सेलाइन ड्रॉप्स, एक साल की उम्र के बाद शहद देना और स्पष्ट चेतावनी

संकेतों को बूझना, जिन्हें चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है, जैसे उपायों से हो सकती है। माता-पिता को यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर खांसी एक संक्रमण रोग है, अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए सिरप की जरूरत नहीं होती।

दूसरा, उत्पादन नियमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्रत्येक पी जाने वाली दवा, जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटोल जैसे सहायक पदार्थ शामिल होते हैं, उनकी विषाक्तता की अनिवार्य जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता लाइसेंस धारक हों, और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। राज्य औषधि नियामकों को प्रशिक्षित निरीक्षकों, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और दबाव से मुक्ति की आवश्यकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर केवल अस्थायी निलंबन ही नहीं, बल्कि मुकदमा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए।

तीसरा, विषाक्ता का पता लगने पर शेष दवा को बाज़ार से तुरंत हटाने वाली प्रणाली होना जरूरी है। एक बार दूषित उत्पाद का संदेह होने पर, सूचना दिनों की बजाय घंटों में प्रसारित होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय डिजिटल दवा रिकॉल प्लेटफॉर्म हो, जोकि बैच नंबर, फार्मेसियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और आम जनता से जुड़ा हो, इससे कई जानें बच सकती हैं। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से माता-पिता निर्माता, बैच नंबर, समाप्ति तिथि और रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकें।

चौथा, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। परामर्श पर्ची में बीमारी की शिनाख़्त, उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा और कितने समय तक दवा देनी है, यह सब दर्ज हो। खांसी की मिश्रित दवाएं (कॉम्बिनेशन सिरप) का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। दवा विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए, तीमारदारों को जानकारी युक्त करना और असुरक्षित मांगों को साफ इंकार कर देना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि आसानी से समझ आने वाली और व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करें, जिनका पालन व्यस्त क्लीनिक और फार्मेसियों में किया जाना है। आखिर में, समुदायों को भागीदार के तौर पर लिया जाना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कर्मी, 'आशा' कर्मी, स्कूल अध्यापक, बच्चों के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर और लोकल मीडिया तीन आसान बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं : छोटे बच्चों को खुद से तय करके दवा न दें; पुरानी सिरप पर्ची का दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर किसी दवा सेवन के बाद बच्चे को पेशाब कम आए, लगातार उल्टी हो, सुस्ती छाए, सांस तेज़ चले या बीमारी और बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पंचायतें और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 'सुरक्षित दवा दिवस' मना सकते हैं, जिनमें परिवार दवाइयों को सुरक्षित तरीके से जांचना, रखना और फेंकना सीख सकें।

अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ़ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण शृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसा दवा प्रणाली बनाना है जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की ज़िम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें। सवाल यह भी है कि क्या भारत घटना-आधारित उपाय करने से हटकर रोज़मर्रा की दवा-सुरक्षा की ओर बढ़ सकता है।

आस्था पर आघात है चढ़ावा चोरी

सदियों के संघर्ष, असंख्य लोगों के बलिदान और दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में साकार हुए राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले ने लोगों की आस्था पर गहरी चोट करने के साथ ही उनके भरोसे को डिगाने का काम किया है। किसी के लिए भी यह सोचना कठिन है कि चढ़ावे में चोरी वही लोग कर रहे थे, जिन पर उसकी पाई-पाई का हिसाब रखने की जिम्मेदारी थी। इस हैरान-परेशान करने वाले मामले की जांच एसआइटी की ओर से की जा रही है। आशा की जाती है कि सच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जब तक ऐसा हो न जाए, तब तक निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता।

कहना कठिन है कि चढ़ावे में चोरी कब से हो रही थी, लेकिन यह विचित्र है कि सबसे पहले इसकी भनक स्थानीय विपक्षी नेताओं को लगी और फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सार्वजनिक किया। जब ऐसा हुआ तो मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सब कुछ ठीक होने का दावा कर दान राशि में किसी तरह की हेराफेरी से इन्कार कर दिया। आखिर उन्हें ऐसा करने की जल्दी क्या थी? इस इन्कार के बाद यह सामने आया कि कुछ लोगों के ठिकानों से पैसा मिला। यह भी पता चला कि जो लोग दान राशि की गिनती में शामिल थे, उनकी आर्थिक हैसियत अचानक अच्छी हो गई थी और वे लाखों-करोड़ों की जमीन खरीद रहे थे। ऐसी बातें भी सामने आईं कि जिन लोगों ने भगवान राम को आभूषण आदि अर्पित किए, उन्हें दान की रसीद नहीं दी गई और कुछ से यह कहा गया कि उन्होंने भेंट स्वरूप चांदी या सोने का जो कुछ दिया था, उसे गला दिया गया।

यह भी सामने आया कि दान पात्रों की निगरानी और दान राशि की गणना भी सही तरह नहीं हो रही थी। जब कथित आंतरिक जांच में गंभीर किस्म की गड़बड़ी सामने आई तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार से जांच कराने को कहा गया। इसके बाद एसआइटी का गठन हुआ। इसके पहले राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र यह कह रहे थे कि उनका काम केवल निर्माण कार्यों को देखना है, वे अचानक टीवी चैनलों में यह बताते हुए दिखाई दिए कि दान पात्रों की निगरानी और चौकसी में भारी कमी थी। उन्होंने चढ़ावा चोरी को डकैती कह कर स्वत: ही मामले की गंभीरता को रेखांकित कर दिया। उन्होंने इसकी भी जरूरत जतानी शुरू कर दी कि मंदिर प्रबंधन की देख-रेख के लिए किसी सीईओ की नियुक्ति आवश्यक है। आखिर इसकी आवश्यकता पहले क्यों नहीं महसूस की गई? वास्तव में ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं।

समझना कठिन है कि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मंदिर की व्यवस्था के संचालन में सक्रिय क्यों नहीं थे? ऐसा क्यों लगता है कि कुछ सदस्य केवल नाममात्र के सदस्य थे? क्या ऐसा इसलिए था कि कुछ लोगों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था? सच जो भी हो, यह विचित्र है कि करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात पहुंचाने वाले इस मामले के सामने आने के बाद किसी ने भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने का साहस नहीं दिखाया। किसी ने भी जांच होने तक ही सही, अपना

पद छोड़ने की पेशकश भी नहीं की।

इतने विख्यात और प्रतिष्ठित मंदिर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों को नैतिकता का परिचय देने के लिए तत्पर रहना चाहिए था। राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर है। इस मंदिर के व्यवस्थापकों को तो उच्च स्तर की मर्यादा दिखानी चाहिए थी। क्या वे तभी अपना पद छोड़ेंगे, जब एसआइटी उनकी भूमिका संदिग्ध करार देगी या फिर वे पुलिस जांच में गुनहगार दिखने लगेंगे? इस मामले में अभी तक कोई एफआइआर दर्ज न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। जब मामले की तह तक पहुंचने के लिए देर-सबेर यह काम करना ही होगा, तो फिर इसमें देरी का क्या औचित्य? यह ऐसा मामला नहीं कि चढ़ावे के हिसाब-किताब और उसकी देखरेख संबंधी कमियों को ठीक कर देने से कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का पाप किया है, उन्हें कठोर दंड का भागीदार बनाए और जिनकी लापरवाही से ऐसा हुआ, उन्हें व्यवस्था से बाहर किए बिना भरोसे की बहाली होने वाली नहीं है। भरोसे की बहाली के लिए जो कुछ भी संभव है, किया जाना चाहिए।

आवश्यक हो तो राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए और उसे नए सिरे से गठित किया जाए, क्योंकि मामला करोड़ों रुपये की हेराफेरी का ही नहीं, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं हो सकती कि जिस मंदिर का प्रबंधन आदर्श तरीके से होना चाहिए था, वहां भी ऐसा नहीं किया जा रहा था। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा था, इसके लिए जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। यह खेद की बात है कि अभी तक इस जरूरत की न्यूनतम पूर्ति भी नहीं हुई।

विशेष आलेख /राशिफल

कमजोर मानसून का विकास दर पर असर

कमजोर मानसून और अल-नीनो के खतरे के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण को मजबूत करना होगा। भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक 'सुरक्षा कवच' की तरह है।

आरबीआई द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने से देश की कृषि और विकास दर पर असर पड़ सकता है। इस समय जून माह में समय से पीछे चल रहे मानसून ने खरीफ फसलों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक करीब 42 प्रतिशत बारिश कम होने से नकदी फसलें कपास और सोयाबीन बुवाई के आरंभिक दौर में पिछड़ गई हैं। ऐसे में कृषि तथा अर्थव्यवस्था के सामने अल-नीनो और कमजोर मानसून से सूखे की आशंका तथा महंगाई की चुनौतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2026 में भारत अल-नीनो से अत्यधिक प्रभावित होगा। कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति कृषि, जल आपूर्ति और महंगाई के परिदृश्य पर चुनौतियां निर्मित करते हुए दिखाई देगी। इससे पहले वर्ष 2015 में भारत में अत्यधिक कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उस समय मानसून सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम था। इस वर्ष मानसून के दौरान अल-नीनो की स्थिति मजबूत होने की वजह से बारिश अत्यधिक कम होगी। इतना ही नहीं, जलाशयों के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। यह परिदृश्य भारत द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लक्षित विकास दर को बनाए रखने के लिए एक चुनौती दिखाई दे रहा है। नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल

रकबे का केवल 55 प्रतिशत सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है। सीडब्ल्यूएमआई के अनुसार, लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल-संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मानसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी हुई है।

मौजूदा परिदृश्य देश के वर्तमान सुकूनदायक कृषि क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। कम बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना होगा। कमजोर मानसून और अल-नीनो के खतरे के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण को मजबूत करना होगा। भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक 'सुरक्षा कवच' की तरह है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण बहुत कम प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के लिए हथियार बन गए थे। इसलिए गेहूं के आगामी किसी भी नए निर्यात आदेश की पूर्ति के लिए सजगता रखनी होगी। चूंकि इस साल खरीफ सीजन की बुवाई शुरू से ही कम रहने से देश के किसानों और नीति-निर्माताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों का सबसे खराब और सूखा मानसून देखने को मिल सकता है। अल-नीनो के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून, 2026 से देशव्यापी 'खेत बचाओ' अभियान के तहत रणनीतिपूर्वक कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत किसानों को उनके इलाके और फसल के हिसाब से खास सलाह दी जा रही है, ताकि वे मौसम के जोखिमों को समझकर सही निर्णय ले सकें। इसके साथ-साथ किसानों को उनके इलाके के मौसम, वहां की मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से कृषि उत्पादन संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष — आपको किसी का पक्ष लेने से बचना चाहिए। किसी के साथ रुपये का लेन-देन नहीं करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है।

सिंह — आपका आज का दिन आनंद और खुशी के पलों में व्यतीत होगा। आप नया कार्य शुरू कर सकेंगे। सहोदरों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य में वृद्धि हो सकती है।

धनु — आपके घर में आनंद का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका समय आनंद और उत्साह में व्यतीत होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेग।

वृषभ — आपका आज का दिन मिश्र फलदायी होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद या मनमुटाव होने की संभावना है। आज आपका मनोबल दृढ़ न होने के कारण निर्णय लेने में तकलीफ होगी।

कन्या — आज का दिन मनोरंजन और मौज-मस्ती में व्यतीत होगा। परिजनों या मित्रों के साथ घूमने या फिल्म देखने जाने की संभावना है। आप अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे।

मकर — आपके निर्धारित कार्य पूरे होंगे। ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा। आप तन-मन से स्वस्थ रहेंगे।

मिथुन — आज अत्यधिक भावुकता आपके मन को आर्द्र बनाएगी। महिला और माताजी से संबंधित चिंताएं रहा करेंगी। प्रवास के लिए उचित समय नहीं है।

तुला — आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। नौकरी में आपकी आय बढ़ेगी। आपके मित्रों और बुजुर्गों से भी आपको लाभ हो सकता है। नए मित्र बनाएंगे और यह मैत्री आगे चलकर लाभदायक साबित होगी।

कुंभ — आज आप विदेश में बसने वाले मित्रों या स्नेहीजनों के अच्छे समाचार पाकर आनंद अनुभव कर सकेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है।

कर्क — आपको अपने मिजाज को काबू में रखना पड़ेगा, ताकि कोई समस्या न हो। बीमार व्यक्ति आज कोई नई उपचार पद्धति न आजमाएं। ऑपरेशन न कराएं।

वृश्चिक — आज आप पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर घरेलू मामलों के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। घर को नए सिरे से योजनाबद्ध करके आप उसे एक नया स्वरूप देंगे।

मीन — आज संतान सम्बंधी मामलों को लेकर चिंता रहेगी। पेट संबंधी परेशानियां होंगी। विद्याध्ययन के लिए समय अनुकूल नहीं है।

एनिमेशन के फील्ड में मौके ही मौके

बदलती तकनीक के साथ अब एनिमेशन की दुनिया भी बदल रही है। एनिमेशन अब और हाइटेक हो रहे हैं। कैरेक्टर पहले से ज्यादा इंसानों की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंटेशन से लेकर 3डी कैरेक्टर तक एनिमेशन की दुनिया में बदलाव आ रहा है। लोगों की गेमिंग में बढ़ती दिलचस्पी के कारण इस फील्ड में खास स्किल रखने वालों की मांग बढ़ रही है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि एनिमेशन की दुनिया में काम करने वाले लोग केवल एक या दो प्रोफाइल के लिए काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यह एक बड़ा फील्ड है, जिसमें कई अलग-अलग प्रोफाइल पर काम करने का मौका मिलता है। एनिमेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। जानते हैं एनिमेशन की दुनिया में कहां मौके मिलते हैं....

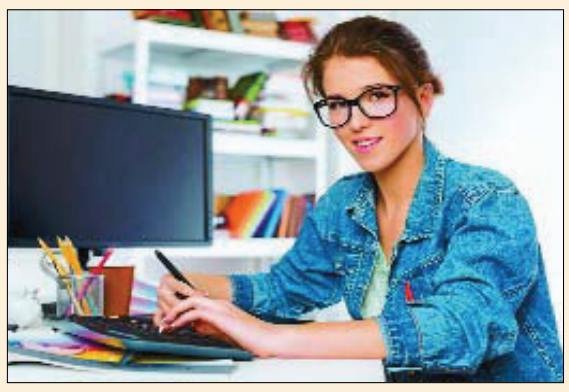

वीडियो गेम डिजाइनर

एक वीडियो गेम डिजाइनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइन की मदद से वीडियो गेम्स तैयार करता है। यह अपने कैरेक्टर के लिए कॉन्सेप्ट तैयार करता है, उसकी स्टोरी लाइन तय करता है, उसका कैरेक्टर किस माहौल में रहता है, यह भी वीडियो गेम डिजाइनर तय करता है। यह बहुत क्रिएटिव वर्क माना जाता है।

3डी आर्टिस्टः किसी चीज के लिए एनिमेशन को तैयार करने के लिए 3डी विजुअलाइजेशन, रेंडरिंग और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये विजुअल इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इस तरह अलग-अलग टीम मिलकर किसी एनिमेशन को आकर्षक बनाती है।

टेक्निकल डायरेक्टरः यह टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ होते हैं, जो एनिमेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर टूल को विकसित करने में मदद करते हैं। ये मॉडलिंग, एनिमेशन, स्पेशनल इफेक्ट, लाइटिंग और रिसर्च के ऑपरेशन प्रोसीजर पर काम करते हैं।

3डी मॉडलर

एनिमेशन की दुनिया में 3डी मॉडलर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इनका काम कार्टून कैरेक्टर की डायमेंशन तय करना, उनके कपड़े, माहौल और सतह को डिजाइन करना होता है। यह कार्टून या एनिमेशन की दुनिया में अहम प्रोफाइल मानी जाती है।

स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट

इलस्ट्रेशन की मदद से स्टोरी तैयार करने का काम स्टोरीबोर्ड आर्टिस्ट करता है। फिल्मों, टीवी शो और कॉमर्शियल तैयार करने में इनकी भूमिका होती है।

कैरेक्टर एनिमेटर

एक कैरेक्टर एनिमेटर अपने कैरेक्टर में जान डालने के लिए एनिमेशन टूल, 3डी मॉडलिंग, 2डी एनिमेशंस और दूसरी एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके कैरेक्टर को तैयार करता है और उसमें एनिमेशन डालकर जान फूंकता है।

एनिमेटर

यह परंपरागत प्रोफाइल है। इसमें काम करने वाला एनिमेटर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर या हाथ से ड्रॉइंग करके आकर्षक मूविंग ऑब्जेक्ट तैयार करता है। इनका इस्तेमाल फिल्म, टीवी प्रोग्राम और वीडियो गेम्स के लिए होता है।

क्या आपमें है एंटरप्रेन्योर बनने की स्किल्स!

स्टार्टअप की सफलता या विफलता काफी हद तक आप पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए या नहीं। इसके लिए जरूरी कि आप अपनी आदतों पर गौर करें। खुद का आकलन करें। इससे आपको पता चलेगा कि किस दिशा में आपको जाना चाहिए...

अधिकतर सफल एंटरप्रेन्योर में कुछ खास बातें होती हैं। अक्सर हम उन्हें इग्नोर करते हैं। उन्हें पहचानने और जीवन में लागू करने की जरूरत है।

लाइटबल्ब मूमेंट

इस शब्द को स्टार्टअप की दुनिया में कामयाब लोगों के लिए काम में लिया जाता है। दरसअल लाइटबल्ब मूमेंट वह होता है, जब आप हमेशा किसी नए आइडिया के बारे में ना केवल सोचते रहते हैं अपितु उसे ड्रॉ भी करते हैं। इसके अलावा आपके चारों ओर क्या हो रहा है और उस परिस्थिति में आपका व्यवहार कैसा है, इस पर विचार करते हैं। आपके दिमाग में किस प्रकार के आइडिया आते हैं और उनका इस्तेमाल आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में कैसे करते हैं। यह सभी लाइटबल्ब

क्या आप अच्छे वक्ता हैं

बिजनेस में कम्युनिकेशन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति कितनी है यह आपकी रियल पर्सनेलिटी का पार्ट नहीं हो सकता है क्योंकि बिजनेस में आपकी रियल प्रजेंस सबसे अधिक प्रभाव डालती है। आप कितने अच्छे स्पीकर हैं और आपके शब्द लोगों को कितना आकर्षित करते हैं आदि बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आप रूल ब्रेकर हैं?

रूल ब्रेकर वर्ड बुद्धिमान लोगों के लिए किया जाता है, जिन्होंने ना केवल अपने नजरिए से दुनिया को देखा अपितु उसमें कुछ हासिल भी किया। क्या आप खुद को उस दुनिया में रख पाते हैं? रूल ब्रेक करने के बाद हमेशा सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसा करने का प्रयास कभी किया है। क्योंकि एक सफल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो लीक से अलग कुछ करने का प्रयास करे। बिजनेस में सफल होने के लिए प्रतिदिन नए आइडिया और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने की जरूरत होती है। आपके कई आइडियाज परफेक्ट हो सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें और पूरे मन से अपना प्रयास करें।

लक्ष्य निर्धारित करें

किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण जरूरी होता है। यदि आप एक बेहतरीन योजनाकार हैं, तो बिजनेस में आपके लिए असीम संभावनाएं हैं। योजना और व्यवस्थित काम करना किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए जरूरी है। लक्ष्य पाने की सफलता दर अब तक आपके जीवन में कितनी रही है इस पर सोचने की जरूरत है। बिजनेस में सफल होने के लिए यह जानना जरूरी है कि लक्ष्य से दूर हुए बिना आप अपने काम को किस तरह जारी रखते हैं।

क्रोमबुक खरीदने से पहले ध्यान दें...

अगर आप सादा, हल्का और सुरक्षित लैपटॉप चाहते हैं, तो क्रोमबुक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन क्रोमबुक खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

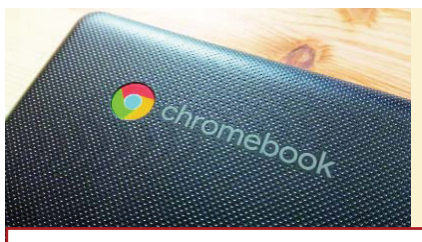

गूगल इकोसिस्टम

क्रोमबुक गूगल के इकोसिस्टम पर निर्भर है। इसका मतलब है कि आपको जीमेल, गूगल ड्राइव और अन्य गूगल सेवाओं का नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अन्य ईमेल सेवाओं या क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।

तेज इंटरनेट कनेक्शन

अधिकांश काम ऑनलाइन करते हैं। इसका मतलब है कि आपको तेज इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। इंटरनेट धीमा है, तो क्रोमबुक का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे।

कुछ ऐप्स नहीं चलेंगे

क्रोमबुक पर सभी विंडोज या मैक ऐप्स काम नहीं करते हैं। आपको कुछ ऐप्स के लिए वैकल्पिक वेब ऐप्स या एंड्रॉयड ऐप्स ढूंढने होंगे। हालांकि वक्त के साथ उनके साथ परिचित हो जाएंगे और आपके सभी काम होने लगेंगे।

बजट का ध्यान

सस्ता क्रोमबुक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन वह हमेशा अच्छा प्रदर्शन करे, यह जरूरी नहीं! यदि अधिक शक्तिशाली क्रोमबुक चाहिए, तो आपको थोड़ा अधिक खर्च करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए।

सुरक्षा के मामले में बेहतरीन

क्रोमबुक बहुत सुरक्षित होते हैं। वे मैलवेयर और वायरस के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। विंडोज पर मैलवेयर बहुत अधिक हैं और इस मामले में यह आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

कुछ शर्तों के साथ गेमिंग

क्रोमबुक पर गेमिंग संभव है, लेकिन यह विंडोज पीसी जितना शक्तिशाली नहीं है। आप कुछ हल्के गेम या क्लाउड गेमिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

कुछ ही मिनट में अपडेट

क्रोमबुक अपडेट बहुत तेज होते हैं। लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता। आमतौर पर अपडेट भी छोटे होते हैं।

बहनों ने 20 हजार किलो चीड़ की सुइयों से बनाए हैंडीक्राफ्ट

उत्तराखंड की दो बहनें नूपुर और शारवरी चीड़ की सुइयों से हैंडीक्राफ्ट तैयार कर रही हैं, साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से भी बचा रही हैं। अपनी इस पहल के जरिए वे राज्य की 100 ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। दोनों ने मिलकर साल 2021 में इसकी शुरुआत की। उत्तराखंड में कई बार चीड़ की कांटेदार सुइयों के कारण जंगलों में आग भड़की और कई लोगों की मौत हुई। सरकार इनसे निपटने के लिए कोशिशें कर रही है। दोनों बहनों ने इसका समाधान खोजा और इनसे हैंडीक्राफ्ट तैयार करना शुरू किया और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी दिया। इस तरह पेड़ से टूटकर गिरने वाली इन कांटेदार सुइयों का सही इस्तेमाल हो रहा है।

जीमेल के नए जेमिनी-पावर्ड फीचर से मेल करना हुआ और आसान

गूगल अपने सभी प्लेटफॉर्म पर जेमिनी एआइ को शामिल कर रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब आइफोन पर जीमेल यूजर्स के लिए जेमिनी-संचालित Q&A सुविधा शुरू की जा रही है, जो ईमेल ढूंढना और मैनेज करना काफी आसान बनाती है। कुछ वक्त तक यह सुविधा वेब और एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध थी। अब आइओएस यूजर भी जीमेल पर गूगल के इस नवीनतम एआइ इनोवेशन का आनंद ले सकते हैं।

जीमेल Q&A कैसे काम करता है?

जीमेल की नवीनतम Q&A सुविधा जेमिनी को सीधे इनबॉक्स में शामिल करती है, जहां यह एआइ का इस्तेमाल करके तुरंत ईमेल का विश्लेषण, सर्च और ड्राफ्ट करता है। इसके अलावा इसे किसी विशिष्ट व्यक्ति से अनरीड यानी अपठित ईमेल ढूंढने या किसी ईवेंट या मीटिंग के बारे में विशिष्ट जानकारी वाले ईमेल की सर्च करने जैसे जरूरी सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

जीमेल Q&A कैसे एक्सेस करें?

अगर आपके गूगल अकाउंट में जीमेल Q&A का एक्सेस अवेलेबल है, तो एंड्रॉयड और आइओएस दोनों डिवाइस पर ऊपरी दाएं कोने में जेमिनी लोगो दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने से Q&A विंडो खुलेगी, जो यूजर्स को उनके इनबॉक्स में मौजूद ईमेल से संबंधित सवाल पूछने की अनुमति देती है, जिसमें नया ईमेल ड्राफ्ट करने का ऑप्शन भी है। वेब पर जीमेल यूजर्स साइड पैनल से भी इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बन सकती हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर

यदि आपके अंदर विश्लेषण करने या निर्णय लेने की क्षमता है, तो आपके लिए फाइनेंस सेक्टर में प्रोक्योरमेंट मैनेजर बनने का विकल्प मौजूद है। उत्पादों या सेवाओं को कितने में खरीदना है, उस पर लागत क्या आएगी, इन सबका फैसला प्रोक्योरमेंट मैनेजर ही करता है। महिलाएं यह बखूबी कर सकती हैं।

खरीदार के रूप में अपनी स्किल्स से आप कॅरियर बना सकती हैं।

काम की प्रकृति

एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर को ऐसी प्रक्रियाएं लागू करनी होती हैं, जो दिन-प्रतिदिन के कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यावसायिक परेशानियों को दूर कर सकें। किसी भी संगठन में काम करते समय वह ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का चयन करता है। वह ग्राहकों और वेंडर्स को अपने कौशल से संतुष्ट करता है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में प्रोक्योरमेंट मैनेजर की खूब मांग है।

जरूरी स्किल्स

प्रोक्योरमेंट मैनेजर बनने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स और काम को जिम्मेदारी के साथ करने का गुण होना चाहिए। कंपनियां उन्हें मौका देती हैं, जिन्होंने फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और परचेजिंग में स्नातक की डिग्री हासिल कर रखी हो।

कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टार्टअप से करें अच्छी कमाई

भारत में अब तोहफे देने का चलन सिर्फ दोस्तों-रिश्तेदारों तक ही सीमित नहीं रहा। फेस्टिवल सीजन से लेकर कर्मचारी के प्रमोशन और वर्क एनिवर्सिरी तक कॉर्पोरेट कल्चर में तोहफे देने का चलन अब बढ़ रहा है। ऐसे में उन लोगों के लिए कई मौके हैं, जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं।

कुछ हटकर सोचें

कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का स्टार्टअप शुरू करना है तो तोहफा ऐसा हो जो कंपनी का असर छोड़े और कर्मचारी को भी पसंद आए। इन दिनों ऐसे तोहफे ट्रेंड में हैं, जो इको फ्रेंडली हों, दिखने में अलग हों और कर्मचारी के काम आएं। आकर्षक तोहफों की ऐसी लिस्ट बनाएं जो कंपनियों के साथ शेयर की जा सके।

मौके के मुताबिक गिफ्ट

आप सबसे पहले मौके को पहचानें और उसके मुताबिक तोहफे तैयार करने की योजना बनाएं। जैसे- कंपनी जॉइन करने, प्रमोशन, दिवाली और कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौनसा तोहफा देना उचित होगा, यह पूरी प्लानिंग करें।

क्वालिटी और पैकेजिंग

कई बार पैकेजिंग बढ़िया होती है, पर जब प्रोडक्ट ओपन किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी देखकर मन खराब हो जाता है। इसलिए आपको गिफ्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग दोनों पर ही बराबर ध्यान देना चाहिए।

टार्गेट ऑडियंस तय करें

आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपकी टार्गेट ऑडियंस क्या है, इसे तय करें। एक बार यह तय करने के बाद उसी के मुताबिक प्लानिंग और प्रोडक्ट तैयार करें। ध्यान रखें कि टार्गेट ऑडियंस तय करते समय उन लोगों से बात भी करें कि वो क्या पसंद-नापसंद करते हैं। इससे आपकी योजना प्रभावी बनाई जा सकेगी। टार्गेट ऑडियंस की पसंद-नापसंद को ध्यान में रखने से आप उनके लिए बेस्ट गिफ्ट्स का सलेक्शन कर पाएंगे। अगर आपके पास गिफ्ट का कोई अच्छा आइडिया है, पर उसकी टार्गेट ऑडियंस का सही तरह से चुनाव नहीं किया गया है, तो आपका आइडिया फ्लॉप भी हो सकता है।

कस्टमाइज गिफ्ट्स सबकी पसंद

इन दिनों कस्टमाइज गिफ्ट्स का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी चाहती है कि उनके कर्मचारी और कंपनी की सोच के मुताबिक तोहफे तैयार हों। जिस पर कंपनी की मुहर, कर्मचारी का नाम और उनकी प्रोफाइल के मुताबिक चीजें शामिल हों। इसलिए जब कंपनी को डील ऑफर करें तो अपनी प्लानिंग के साथ उनकी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज गिफ्ट्स सजेस्ट करें। आपको ऐसे गिफ्ट्स की प्लानिंग करनी चाहिए, जो हर आयु वर्ग के लोगों को पसंद आएं। इसके लिए आपको हर सेग्मेंट में पूरी रिसर्च करना बहुत जरूरी है।

मार्केट रिसर्च है जरूरी

कई कंपनियां कस्टमाइज गिफ्ट्स तैयार करती हैं। इसलिए मार्केट में पहले रिसर्च करें और फिर कदम उठाएं। रिसर्च के बाद इकट्ठा हुई जानकारी के बाद अपनी योजना बनाएंगे, तो वह ज्यादा असरदार साबित होगी।

आवेदन करने के बाद रिक्रूटर जवाब नहीं दे, तो इन बातों पर गौर करें...

जब आप अपना रेज्यूमे लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो क्या आपके पास रिक्रूटमेंट एजेंसी से फोन आता है? कभी गौर किया है कि जॉब से जुड़े प्लेटफॉर्म पर सीवी अपडेट करने के बाद नौकरी का प्रस्ताव आया या नहीं? क्या कई बार आपके सब कुछ करने के बाद भी रिक्रूटर की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। नौकरी के लिए रिक्रूटर पलटकर फोन क्यों नहीं करता? आइए जानते हैं...

आपने आवेदन किया?

कई बार रिक्रूटर के फोन का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सच्चाई तो यह होती है कि आपने नौकरी के लिए सही तरह से आवेदन ही नहीं किया होता है। किसी सोशल नेटवर्क पर खुद को प्रस्तुत करने, पद के लिए खुद की रुचि प्रकट करने या मौखिक रूप से रिक्रूटर से सार्वजनिक प्रोफाइल स्वीकार करने का आग्रह कभी भी मायने नहीं रखता है। यदि जॉब का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है तो ईमेल के आवेदन का रिकॉर्ड और रेज्यूमे की एक प्रति संभालकर रखनी चाहिए।

अव्यवस्थित प्रक्रिया

हो सकता है कि आपने आवेदन की सही प्रक्रिया का पालन किया हो, पर हायरिंग मैनेजर आमतौर पर बहुत ज्यादा बोझ से दबे रहते हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि आपका आवेदन रिक्रूटर तक सही तरह से न पहुंचा हो। इसलिए आपको रिक्रूटर से संपर्क में रहना चाहिए। आवेदन भेजने के दो दिन के अंदर उसकी प्राप्ति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जिस पद के लिए आवेदन किया है, रिक्रूटर तक उसकी जानकारी पहुंच जाए।

आपको रिक्रूटर के काम करने के तरीके को समझना चाहिए। तभी आप सलेक्ट हो पाएंगे। कई बार गलत पद के लिए आवेदन करने या आपसे योग्य व्यक्ति के मौजूद होने के कारण आपको मौका नहीं मिलता है। लेकिन आपको प्रयास तो करते रहने चाहिए।

प्राथमिकताओं में बदलाव

कई बार उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया के बीच में ही कंपनी की प्राथमिकताओं में बदलाव आ जाता है और मौजूदा भर्ती को रोक दिया जाता है। ऐसे में हायरिंग मैनेजर के लिए इस बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है। वह और आप दोनों अपना समय और प्रयास लगा चुके होते हैं। ऐसे में रिक्रूटर सीधे फोन करना बंद कर देता है। इससे आप स्थिति को समझ सकते हैं।

चुने जाने के अवसर

आपको नौकरी के विवरण को सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए। इच्छित योग्यताओं के बारे में सही तरह से विचार करना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या आप नौकरी के लिए आवेदन करने के योग्य हैं या नहीं। हो सकता है कि आप सॉफ्टवेयर डवलपर हों, लेकिन नौकरी में उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही हो, जो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट कंपनी में काम कर चुके हों। ऐसे में अगर हायरिंग मैनेजर के पास पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तब आपको चुना जा सकता है।

प्रतियोगिता बेहतर होती है

बाजार में कई योग्य प्रतियोगी होते हैं। कई बार प्रतियोगिता केवल इस बात की होती है कि अन्य प्रतियोगी के रेज्यूमे में आपके मुकाबले में बेहतर कार्यानुभव, कम वेतन और बेहतर ब्रांड का जिक्र होता है। इस कारण से आपको मौका नहीं मिल पाता है और अन्य व्यक्ति को चुन लिया जाता है।

वाइ-फाइ राउटर खरीदने से पहले ये फीचर्स देखें

इंटरनेट राउटर घर या कार्यालय नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। अगर नया वाइ-फाइ राउटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें ये खूबियां जरूर देखनी चाहिए–

वाइ-फाइ 6इ का सपोर्ट

ज्यादातर राउटर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5गीगाहर्ट्ज दोनों चैनल को सपोर्ट करते हैं। नया राउटर खरीद रहे हैं, तो वाइ-फाइ 6इ का सपोर्ट करने वाला राउटर लें। यह 6गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करता है। इससे अच्छी स्पीड और स्टेबल कनेक्शन मिलता है।

न्यूनतम तीन इथरनेट पोर्ट

स्मार्ट टीवी में वायर्ड इथरनेट कनेक्शन बेहतर है। इससे टीवी पर 4के सामग्री स्ट्रीम करते समय बफरिंग नहीं होती है। वाइ-फाइ राउटर पर न्यूनतम तीन से चार इथरनेट पोर्ट होना जरूरी है।

डब्ल्यूपीए3 सपोर्ट

2004 में लॉन्च किया गया डब्ल्यूपीए2 प्रोटोकॉल अब काफी हद तक अप्रचलित है। इसमें कई कमजोरियां और सुरक्षा समस्याएं हैं, खासकर यदि आप सार्वजनिक वाइ-फाइ का इस्तेमाल कर रहे हों। जबकि 2018 में आया डब्ल्यूपीए3 घर और वाणिज्यिक दोनों के लिए बेहतर है। यह डिवाइस और एक्सेस पॉइंट (आपका राउटर) के बीच बेहतर एन्क्रिप्शन देता है।

पैरेंटल कंट्रोल

यदि घर में बच्चे हैं, तो राउटर पर पैरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स जरूरी है। इंटरनेट खतरनाक हो सकता है, और इसके खिलाफ बचाव अपने राउटर पर नियंत्रण है। पैरेंटल कंट्रोल से अपने हिसाब से वेबसाइट्स और सेवाओं को ब्लॉक कर सकते हैं। ध्यान रखें राउटर पर पैरेंटल कंट्रोल फीचर हो।

फुल टाइम से हाइब्रिड तक, महिलाओं को नौकरी देता है यह प्लेटफॉर्म

एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, जो खासतौर पर महिलाओं के लिए बनाया गया है। यहां महिलाओं को सुविधा के मुताबिक, नौकरी मिलने का दावा किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है- www.herkey.com। जॉब सेक्शन में वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड, फुल टाइम और पार्ट टाइम जैसे विकल्प मिलते हैं। आप अपनी सुविधा के मुताबिक ऑप्शन चुन सकती हैं। विकल्प का चुनाव करने से पहले पूरी सावधानी से जानकारी पढ़ें।

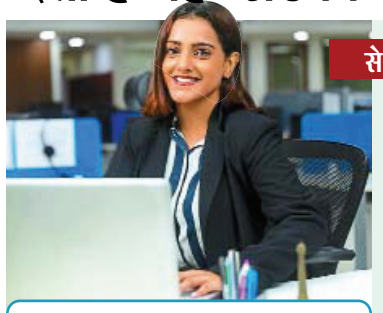

कंपनियों की लिस्टिंग

वेबसाइट पर टाटा ग्रुप से लेकर डायचे बैंक तक सैकड़ों कंपनियों की लिस्ट मिलेगी। आप अपनी योग्यता, स्किल और अनुभव के आधार पर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा कई अन्य विकल्प भी प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं।

सेशंस उपलब्ध

प्लेटफॉर्म पर सेशन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके जरिए महिलाओं को गाइड किया जाता है। जिसके जरिए विशेषज्ञ अपनी बात कहते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं। इसके अलावा महिलाओं को स्किल बढ़ाने का मौका मिलता है।

वाहन चालक को धूप में गर्मी से बचाता सिस्टम, बॉडी करता कूल

महाराष्ट्र के जलगांव के रहने वाले सूफियान मोहम्मद हनीफ पटेल ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जो वाहन चालक को अधिक गर्मी से बचाता है। उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया है कि जब गर्मी तेज होगी, तो दोपहिया वाहन चालक को गर्मी कम लगेगी। उनके इस प्रयोग को काफी सराहा गया है। इसके लिए उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अवॉर्ड 2023 दिया गया। इनोवेटिव माइंड सीरीज इसी पहल का हिस्सा है। सूफियान महाराष्ट्र के भुसावल के ताप्ती पब्लिक स्कूल में 8वीं के स्टूडेंट हैं।

ऐसे काम करता है सिस्टम

इस सिस्टम को दोपहिया वाहन में लगाया गया है। इस सिस्टम में लगा कम्प्रेसर वाहन के इंजन से चलता है और कूलिंग प्रोसेस को शुरू करता है। यह गर्मी को सोखकर ठंडी हवा रिलीज करता है। यह ठंडी हवा वाहनचालक की जैकेट में पहुंचती है। इसमें सुरक्षा के तौर पर अलार्म और मोबाइल फोन सेफ्टी सिस्टम भी जोड़ा गया है।

साभारः हनीबी नेटवर्क विद सृष्टि एंड जीआइएएन

संक्षिप्त समाचार

बैंक जाने से पहले देखें छुट्टियों की लिस्ट, इस हफ्ते लगातार तीन दिन रहेंगे बंद

नई दिल्ली, एजेंसी। अगर इस हफ्ते आप किसी काम से बैंक जाने वाले हैं तो आपको ब्रांच में कब-कब हॉलिडे रहेगा इसके बारे में पता होना

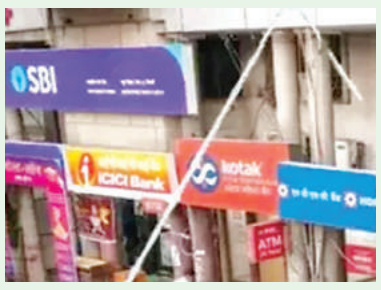

चाहिए। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर सहित देशभर में इस हफ्ते लगातार तीन दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जून को मुहर्रम होने की वजह से बैंक में काम-काज नहीं होगा और 27 जून को महीने का चौथा शनिवार पड़ रहा है इसलिए बैंक हॉलिडे रहेगा। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नियम के मुताबिक, बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे सटरडे को अवकाश रहता है। वहीं, 28 जून को रविवार पड़ने के कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद होने पर कैसे हो सकता है आपका काम? अगर आपके शहर में बैंक बंद हैं तो टेंशन मत लो। ब्रांच बंद रहेगी, लेकिन डिजिटल बैंकिंग तो चालू ही रहेंगी। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक ऐप जैसी डिजिटल सेवाएं 24×7 चलती रहती हैं। इस माध्यम से आप पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट और बैलेंस चेक भी कर सकते हैं। कैश जमा करने के लिए बैंकों के बाहर लगी मशीन का इस्तेमाल करें। एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा भी हमेशा की तरह मिलती रहेगी।

सुबह धूल तो दोपहर में ओजोन गैस बनी सबसे बड़ी चुनौती

नई दिल्ली, एजेंसी। गर्मियों के मौसम में दिल्ली की तपती धूप न सिर्फ तापमान बढ़ा रही है,

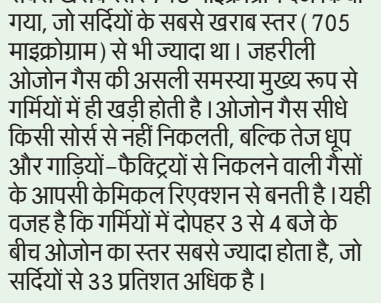

बल्कि हवा में प्रदूषण के पैटर्न को भी बदल रही है। शोध संस्था ''एनवायरोकैटालिस्ट्स'' और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के ताजा विश्लेषण से पता चला है कि गर्मियों में प्रदूषण का स्तर पूरे दिन एक जैसा नहीं रहता। सुबह के समय गाड़ियों का ट्रैफिक और उड़ती धूल जहां हवा खराब कर रही है, वहीं दोपहर में तेज धूप के कारण ओजोन गैस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऐसे में प्रदूषण से निपटने के लिए अब दिन के घंटों के हिसाब से ''टाइम-स्पेसिफिक'' तैयारी करनी होगी। इस अध्ययन में गर्मियों (अप्रैल-जून 2026) के मुख्य प्रभाव और सर्दियों (दिसंबर 2025-जनवरी 2026) के संदर्भ के साथ पीएम 2.5, पीएम 10 और ओजोन के व्यवहार को देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक, बारीक प्रदूषण यानी पीएम 2.5 गर्मियों में सुबह 9 बजे ट्रैफिक शुरू होने पर 77 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के स्तर पर पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यही प्रदूषण आधी रात के वक्त 244 माइक्रोग्राम के चरम स्तर पर रहता है। इसी तरह, मोटे कणों वाला प्रदूषण (पीएम 10) गर्मियों में भी बड़ी मुसीबत बना हुआ है। उड़ती धूल के कारण सुबह 9 से 10 बजे और आधी रात को पीएम 10 का स्तर काफी बढ़ जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि गर्मियों में एक घंटे के दौरान पीएम 10 का सबसे खराब स्तर 718 माइक्रोग्राम दर्ज किया गया, जो सर्दियों के सबसे खराब स्तर (705 माइक्रोग्राम) से भी ज्यादा था। जहरीली ओजोन गैस की असली समस्या मुख्य रूप से गर्मियों में ही खड़ी होती है। ओजोन गैस सीधे किसी सोर्स से नहीं निकलती, बल्कि तेज धूप और गाड़ियों-फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसों के आपसी केमिकल रिएक्शन से बनती है। यही वजह है कि गर्मियों में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच ओजोन का स्तर सबसे ज्यादा होता है, जो सर्दियों से 33 प्रतिशत अधिक है।

दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश से बदला मौसम, 29 जून तक गर्मी से राहत के आसार

29 जून तक बनी रहेगी ऐसी स्थिति

नई दिल्ली, एजेंसी। दोपहर बाद राजधानी में मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गर्जन वाले बादल बनने का था, लेकिन तेज रफ्तार आंधी और उसके बाद हुई वर्षा ने सभी को हैरत में डाल दिया। इससे गर्मी कुछ कम हुई तो दिल्लीवासियों ने भी राहत महसूस की। अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है।

मंगलवार को सुबह आसमान साफ था। तेज धूप भी निकल आई थी, जो दिन चढ़ने के बाद और तीखी होती गई। दोपहर बजे के पश्चात मौसम ने एकाएक करवट ले ली। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते धूल भरी तेज आंधी चलने लगी, जिसकी रफ्तार पालम में सर्वाधिक 91 किमी प्रति घंटे तक दर्ज की गई।

इस दौरान दोपहर दो से ढाई बजे के बीच आइजीआइ एयरपोर्ट पर दृश्यता का स्तर छह हजार मीटर से घटकर महज 800 मीटर रह गया। इतना ही नहीं, इस दौरान अलग अलग जगहों पर तापमान

में भी लगभग 15 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि ओवर आल मंगलवार का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान ज्यादा ही रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 40.1 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 92 से 28 प्रतिशत रहा। वर्षा शाम साढ़े पांच बजे तक 8.4 मिमी रिकॉर्ड की गई।

स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने बताया कि मौसम में अचानक आए इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ बनने के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर के आसपास के कुछ ट्रफ गुजरना भी रहा। कमोबेश ऐसी ही स्थिति 29 जून तक बनी रहेगी। हालांकि तापमान में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा।

एलजी ने दिए अभियान तेज करने के निर्देश

टीबी उन्मूलन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रही दिल्ली

नई दिल्ली, एजेंसी। टीबी उन्मूलन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रही है दिल्ली। दिल्ली ने 88 प्रतिशत अपफ्रंट एनएएटी (न्यूक्लिक एसिड

एम्प्लीफिकेशन टेस्ट) जांच और 47 प्रतिशत टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) कवरेज हासिल किया गया है, जो शुरुआती पहचान और रोकथाम के प्रयासों को दर्शाता है। भारत अभियान' की प्रगति की समीक्षा में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को दी। उन्होंने टीबी नियंत्रण कार्यक्रम को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि निक्षय पोषण योजना के तहत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान तेज किया जाए। साथ ही उच्च जोखिम वाले वार्डों में एक्स-रे स्क्रीनिंग को और प्रभावी बनाने के लिए परिचालन संबंधी बाधाओं को दूर करने पर भी जोर दिया जाए। बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'टीबी मुक्त भारत' के संकल्प के अनुरूप दिल्ली सरकार शीघ्र पहचान, समय पर उपचार, सामुदायिक भागीदारी और सभी नागरिकों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग को अभियान की गति बनाए रखते हुए टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में प्रयास तेज करने के निर्देश दिए गए।

संपत्तिकर के साथ अब ऑनलाइन मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, एमसीडी की नई व्यवस्था से दिल्ली के 50 हजार दुकानदारों को राहत

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के व्यापारियों और दुकानदारों को जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) को लेकर बड़ी राहत मिली है। एमसीडी ने संपत्तिकर के साथ ट्रेड लाइसेंस को जोड़ दिया है। अब व्यापारी संपत्तिकर के साथ सिर्फ 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देकर इंटरनेट माध्यम से जीटीएल ले सकेंगे। एमसीडी के अनुसार, व्यापारी और दुकानदार 30 जून तक छूट के साथ संपत्तिकर जमा करा सकते हैं। उसके बाद भी संपत्तिकर का 15 प्रतिशत जमा कराकर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। एमसीडी की इस पहल से दिल्ली के करीब 50 हजार दुकानदारों को लाभ होगा। उन्होंने इंस्पेक्टरराज तथा कागजी कार्रवाई की जटील प्रक्रिया से राहत मिलेगी। हालांकि, पहले दिन जीटीएल जमा करने की प्रक्रिया में विसंगतियां भी सामने आई। कुछ दुकानदारों ने इस वर्ष के शुल्क भुगतान की जगह वेबसाइट पर पिछले वर्ष का शुल्क भुगतान दिखने का मामला बताया। कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने इस वित्तीय वर्ष के लिए जीटीएल भरा है लेकिन इंटरनेट माध्यम से मिली रसीद में भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष यानि वर्ष 2025-26 का दिख रहा है।

मूनक नहर में डूबे दो दोस्तों के शव 30 घंटे बाद बरामद, परिवारों में पसरा मातम

नई दिल्ली, एजेंसी। बवाना इलाके में स्थित मूनक नहर में नहाने गए प्रशांत और सत्यम का शव बवाना हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर नहर से बरामद हुआ। इनमें से प्रशांत का शव सोमवार की देर रात्रि और सत्यम का शव मंगलवार की सुबह को बरामद किया गया। इस घटना के बाद परिजनों के बीच मातम पसरा हुआ है हालांकि दोनों का अंतिम संस्कार नांगलोई के समीप श्मशान घाट पर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, रविवार शाम को हुई घटना के बाद सोमवार और मंगलवार को भी सर्च अभियान चलाया गया था जिसके बाद दोनों के शव बरामद हुए ।एनडीआरएफ और बोट क्लब के गोताखोर करीब 30 घंटे तक अधिक समय तक तलाशी अभियान चलाया। रविवार शाम को हुई इस घटना में नहर में डूबे दोनों युवकों सत्यम और प्रशांत का पहले कुछ पता नहीं चल पा रहा था जबकि मनीष इस घटना में बाल बाल बच गया था। प्रशांत, सत्यम और मनीष तिवारी तीनों दोस्त हैं और घटना के वक्त स्कूटी से नहर किनारे पहुंचे थे। बताया जाता है कुछ समय बाद सभी नहर में नहाने के लिए उतरे। लेकिन इस दौरान अचानक गहराई वाले हिस्से में पहुंचने के बाद इन लोगों का संतुलन बिगड़ गया और तीनों पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। वहां मौजूद कुछ लड़कों ने तुरंत मदद की कोशिश की और रस्सी के सहारे मनीष को किसी तरह से बाहर निकाल लिया। जबकि प्रशांत और सत्यम बाहर नहीं निकल पाए थे । डूबे हुए दोनों दोस्तों की पहचान गांव बहरिया, प्रयागराज निवासी सत्यम (20) और कुंडा, प्रतापगढ़ निवासी प्रशांत पांडेय (19) के रूप में हुई है।

दावे बड़े, हकीकत खोखली: दिल्ली में बारिश का पानी नहीं सहेज पा रहे सरकारी रेन हार्वेस्टिंग प्लांट

नई दिल्ली, एजेंसी। द्वारका, नजफगढ़, महरौली, पूर्वी और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई हिस्से भूजल संकट से जूझ रहे हैं। ये वही क्षेत्र हैं जहां वर्षों से सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सरकारी परिसरों में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) संरचनाएं स्थापित होने के दावे सरकारी दावे हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि हजारों सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन व्यवस्था है तो इन क्षेत्रों में भूजल की दयनीय स्थिति क्यों बनी हुई है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के अनुसार दिल्ली की 34 भूजल आकलन इकाइयों में से 13 ओवर-एक्सप्लाइटेड और 12 क्रिटिकल श्रेणी में हैं। ओवर-एक्सप्लाइटेड का अर्थ है कि जितना भूजल जमीन में वापस पहुंच रहा है, उससे अधिक निकाला जा रहा है,

जबकि क्रिटिकल श्रेणी उन क्षेत्रों को दर्शाती है जहां भूजल दोहन चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। पड़ताल में सामने आया कि राजधानी में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों ने बड़े पैमाने पर संरचनाएं स्थापित हैं। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के करीब 9,148 सरकारी भवनों में से 7,596 में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित है। इसके अलावा 500 नए सिस्टम विकसित करने और 1,000 पुराने सिस्टम को पुनर्जीवित किया जा रहा है।

27 वर्षीय भारतीय महिला ने जीता फ्री लग्जरी अपार्टमेंट

दुबई , एजेंसी। दुबई में रहने वाली 27 वर्षीय भारतीय महिला की किस्मत उस समय चमक गई जब उसने एक शॉपिंग कैंपेन के जरिए मुफ्त में एक स्टूडियो अपार्टमेंट जीत लिया। केरल मूल की आयशा अमीर इस विशेष आवासीय अभियान की पहली विजेता बनी हैं, जिसे दुबई में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया है।

जानकारी के अनुसार, आयशा ने शहर में खरीदारी के दौरान एक लकी ड्रॉ में हिस्सा लिया था। इस अभियान के तहत ग्राहकों को भाग लेने वाले स्टोर्स से कम से कम 500 दिरहम की खरीदारी करनी होती है। इसके बाद क्यूआर कोड स्कैन कर खरीदारी की रसीद अपलोड करनी होती है, जिससे उनका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाता है।

आयशा ने बताया कि उन्हें इस अभियान की जानकारी उनके पति ने दी थी। उन्होंने मॉल और सोशल मीडिया पर इसके विज्ञापन देखे थे, जिसके बाद आयशा ने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। जब उन्हें जीत की सूचना देने के लिए फोन आया तो शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद कोई धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बाद में आयोजकों की ओर से आधिकारिक ईमेल और जरूरी जानकारी मिलने के बाद उन्हें यकीन हुआ कि उन्होंने वास्तव में एक लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट जीत लिया है।

आयशा और उनके पति पिछले साल विवाह बंधन में बंधे थे और भविष्य में अपना घर खरीदने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस साल क्षेत्रीय परिस्थितियों और अनिश्चितताओं के कारण उन्होंने फिलहाल अपना फैसला टाल दिया था। ऐसे में

मुफ्त अपार्टमेंट जीतना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग दूसरों को बड़े इनाम जीतते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा उनके साथ कभी नहीं होगा। लेकिन उनकी जीत यह साबित करती है कि कभी-कभी किस्मत अप्रत्याशित तरीके से भी दरवाजा खटखटा सकती है। इस अभियान के तहत कुल 12 अपार्टमेंट विजेताओं को दिए जाएंगे। अगस्त के अंत तक हर सप्ताह नए विजेताओं की घोषणा की जाएगी। इस पहल में करीब 1,000 ब्रांड और 4,000 से अधिक रिटेल आउटलेट शामिल हैं। आयोजकों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ खरीदारी को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि दुबई के निवासियों और ग्राहकों को खास अनुभव देना भी है। सरल प्रक्रिया और आकर्षक इनामों के कारण यह कैंपेन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

ग्रीन कार्ड धारकों की बढ़ीं मुश्किलें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला- अपराध किया तो मिलेगा देश निकाला

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक अहम फैसला दिया, जिससे अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्ड धारकों की परेशानी बढ़ना तय है। दरअसल इस फैसले के बाद अगर कोई ग्रीन कार्ड धारक नैतिक पतन से जुड़ा अपराध करता है तो उसे स्थायी नागरिक होने के बाद भी अमेरिका से निर्वासित किया जा सकेगा। अमेरिका के सीमा सुरक्षा अधिकारियों को अब ऐसे लोगों को अमेरिका से निकालना आसान होगा। अमेरिकी न्यायाधीश क्लेरेंस थॉमस ने फैसले में कहा कि आव्रजन अधिकारियों को अब स्पष्ट सबूतों की जरूरत नहीं होगी और अगर उन्हें लगता है कि अपराध हुआ है तो भी वे कार्रवाई कर सकते हैं। जज ने कहा कि अप्रवासन और नेशनलिटी एक्ट में सबूतों की जरूरत की बात नहीं है। दरअसल एक याचिकाकर्ता मुक चोइ लाउ ने अपनी याचिका में बताया कि वह चीनी नागरिक है, लेकिन उसके पास अमेरिका में स्थायी निवास के लिए ग्रीन कार्ड है। ट्रेडमार्क में जालसाजी के आरोप में लाउ को साल 2012 में चीन से लौटते समय न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश नहीं दिया गया था। हालांकि उस समय उन्हें सशर्त प्रवेश की मंजूरी दी गई। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, लाउ ने बाद में जाली नोट बनाने के आरोपों को भी स्वीकार किया।

मिसाइलों के दम पर बचा ईरान

राष्ट्रपति पेजेशकियन बोले- यूएस के साथ समझौते में शामिल नहीं हमारा मिसाइल कार्यक्रम

इस्लामाबाद, एजेंसी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के साथ हुए 14 सूत्रीय समझौते का हिस्सा नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी मिसाइलों को लेकर ऐसा कोई समझौता नहीं होगा। पेजेशकियन ने यह बात पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मीडिया वार्ता के दौरान कही। राष्ट्रपति ने अपने देश के मिसाइल कार्यक्रम का पुरजोर बचाव किया। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें ईरान की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। उनके मुताबिक, अगर ईरान के पास ये मिसाइलें नहीं होतीं, तो इस्त्रायल और अमेरिका अब तक ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर चुके होते। उन्होंने मिसाइल क्षमता और अमेरिका के साथ हुए समझौते के बीच किसी भी तरह के जुड़ाव को सिरे से खारिज कर दिया। पेजेशकियन इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वहां वे पाकिस्तानी नेताओं के साथ आपसी संबंधों और क्षेत्र के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। यह बयान स्विट्जरलैंड में हुई तकनीकी बातचीत के खत्म होने के बाद आया है। इस 14 सूत्रीय समझौते का मुख्य उद्देश्य इलाके में जारी तनाव और दुश्मनी को खत्म करना है। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने इस समझौते का आधिकारिक मसौदा सबके सामने रखा था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस समझौते में कई अहम बातें शामिल हैं। इसमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का प्रावधान है। साथ ही ईरान पर लगी कुछ आर्थिक पाबंदियों को कम करने की बात भी कही गई है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भविष्य में तकनीकी बातचीत करने की रूपरेखा भी तैयार की गई है।

हालांकि, इस आधिकारिक दस्तावेज में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह की रोक का जिक्र नहीं है। इसमें हथियारों से जुड़ी सिर्फ एक ही शर्त है।

रूस से तेल-कोयले की सप्लाई के लिए भारत का नया दांव, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर बना नई लाइफलाइन

मास्को , एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होरमुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक श्रृंखलाओं पर दबाव बढ़ गया है। ऐसे समय में भारत और रूस के बीच विकसित किया गया ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में उभर रहा है। यह समुद्री मार्ग भारत के चेन्नई बंदरगाह को रूस के सुदूर पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से जोड़ता है और इसे आर्थिक तथा सामरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने वर्ष 2024 में इस मार्ग को सक्रिय किया था, जब लाल सागर क्षेत्र में हमास-इजरायल संघर्ष के प्रभाव के चलते यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय जहाजों को

निशाना बनाया जा रहा था। अब अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़े क्षेत्रीय तनाव तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में संभावित व्यवधान ने इस समुद्री गलियारे की उपयोगिता को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, ईएमसी के जरिए रूस से भारत आने वाले जहाजों का ट्रांजिट समय लगभग 24 दिन रह जाता है, जबकि पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग से यही यात्रा 40 दिनों से अधिक समय ले सकती है।इससे भारत को रूस से कच्चा तेल, कोकिंग कोल और अन्य महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की तेज और अपेक्षाकृत कम लागत वाली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।भारत की इस्पात और ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में रूस से निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना रणनीतिक आवश्यकता बन गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो ईएमसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता इससे रूस से आने वाले कच्चे माल और ऊर्जा संसाधनों को भारतीय बंदरगाहों से देश के विभिन्न हिस्सों तक तेज़ी और कम लागत में पहुंचाना संभव होगा। यह समुद्री गलियारा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप भी माना जा रहा है। इसके माध्यम से भारत पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपनी आर्थिक और सामरिक भागीदारी मजबूत कर सकता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादक: नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)